निवेशकों के लिए बड़ी सहूलियतों का एलान

यूपी को 'औद्योगिक प्रदेश' बनाने का महाअभियान

सीएम योगी ने की घोषणा

उद्योगों को इस वर्ष 95 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिलाएंगे

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी, 90 दिन में बदल जाएगी श्रेणी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के लिए बड़ी सहूलियतों का एलान करते हुए सोमवार को कहा कि यूपी को 'औद्योगिक प्रदेश' बनाने का महाअभियान शुरू हो गया है। इस वर्ष औद्योगिक इकाइयों को 95 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। 16 हजार करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदनों का निस्तारण 90 दिन में करेगा। कृषि से औद्योगिक श्रेणी में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को घटाकर सर्किल रेट के 35 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत लिया जाएगा। बड़े भूखंडों पर टेलीस्कोप दरों को शामिल करने पर यह शुल्क 14 प्रतिशत रह जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक आस्थानों व औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को दोहरे टैक्स के बोझ से मुक्ति मिलेगी। जिला पंचायतों द्वारा इकट्ठा टैक्स का न्यूनतम 60 प्रतिशत उसी औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही मेरठ की बंद पड़ी कताई मिल की भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी घोषणा की। यह औद्योगिक क्षेत्र यूपीसीडा विकसित करेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि डीएम के स्तर पर मासिक और मंडलायुक्त स्तर पर दो माह में स्थानीय उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठकें की जाएं।

ग्रेटर नोएडा को बनाएंगे उत्तर भारत का लॉजिस्टिक हब

- 20 हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार, जल्द घोषित होगी लैंड नीति

उद्योग जगत के सहयोग से यूपी बनेगा 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था

प्रदेश निवेश योजनाओं, सीएसआर गतिविधियों, नवाचार और उद्यमशीलता के रूप में निवेशकों से सहयोग चाहता है। प्रदेश का तीव्र आर्थिक विकास कर 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में उद्योग जगत का सहयोग चाहिए। - **योगी आदित्यनाथ**

सीएम ने बताया कि विदेशों से अपनी इकाइयां हटाकर यूपी में स्थापित करने के लिए 10 देशों से 50 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव 7,000 करोड़ रुपये के करीब हैं।

फार्मा, डाटा सेंटर व खाद्य प्रसंस्करण नीति जल्द

मुख्यमंत्री ने बताया कि गैर-आईटी आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप नीति के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए यूपी स्टार्ट-अप नीति-2020 तथा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2020 जैसी नई नीतियों की घोषणा कर दी गई है। डाटा सेंटर नीति, फार्मा और नई खाद्य प्रसंस्करण नीति भी जल्द घोषित की जाएंगी।

डिफेंस कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ होगा निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। नए निवेशकों के लिए 20,000 एकड़ का एक लैंड बैंक तैयार है। इसके अलावा एक व्यापक लैंड बैंक पॉलिसी बन रही है।

'यूपी थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो'

प्रदेश के एमएसएमई, निवेश व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि श्रम सुधारों ने अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि 'यूपी थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो'।

डिफेंस, एयरोस्पेस, लॉजिस्टिक, डाटा सेंटर का नया केंद्र बना यूपी

सीएम ने बताया कि पारंपरिक निवेश के अवसरों के साथ सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और नागरिक उड्डयन की असीम संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिफेंस एवं एयरोस्पेस, वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्युटिकल उद्योग राज्य में निवेश के नए केंद्र हैं। दादरी में ग्लोबल मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और बोडाकी में ट्रांसपोर्ट हब, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को उत्तरी भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेंगे। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के साथ ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे के पास का क्षेत्र एक आकर्षक निवेश मंजिल है।

सीएम योगी बोले- नए निवेशकों के साथ पुरानी इकाइयों को ऋण दिलाने का लक्ष्य...पेज 2